मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1672

10.03.2025 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौते

1672. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और उनके अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किए गए नीतिगत परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी), इसके क्योटो प्रोटोकॉल (केपी) और पेरिस समझौते (पीए) का एक पक्षकार है।

(ख) भारत ने नवंबर 2021 में यूएनएफसीसीसी के 26वें सम्मेलन में वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन हासिल करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की। इस लक्ष्य के अनुरूप, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत उर्जा उत्पादन की संस्थापित क्षमता प्राप्त करने के अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अद्यतित लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रहा है।

एमएनआरई नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। तदनुसार, यह मंत्रालय कई योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, जिनमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, सोलर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की योजना तथा 1 गीगावाट क्षमता वाली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विकास, हरित ऊर्जा कॉरिडोर जैसी योजनाएं शामिल हैं।

(ग) अगस्त 2022 में, भारत ने अपने एनडीसी को अद्यतित किया, जिसके अनुसार वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से संचयी विद्युत ऊर्जा उत्पादन की संस्थापित क्षमता का लक्ष्य 50% तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा वर्ष 2030 तक वृक्ष और वन आवरण के माध्यम से 2.5 से 3.0 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित किया जाना है।

भारत ने अपने लिए वर्ष 2070 में निवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत की दीर्घकालिक निम्न-कार्बन विकास कार्यनीति (LT-LeDS) नवंबर 2022 में प्रस्तुत की गई थी। यह कार्यनीति निम्न-कार्बन उत्सर्जन से विकास करने के लिए सात प्रमुख बदलावों पर आधारित है। इनमें शामिल हैं: i) विकास के अनुरूप निम्न- कार्बन उत्सर्जन वाली विद्युत प्रणालियों का विकास, ii) एकीकृत, कुशल और समावेशी परिवहन प्रणाली का विकास, iii) शहरी डिजाइन में अनुकूलन को बढ़ावा देना, भवनों में ऊर्जा और सामग्री के कुशल उपयोग और संधारणीय शहरीकरण, iv) संपूर्ण अर्थव्यवस्था में विकास को उत्सर्जन से अलग करना और एक कुशल, नवीन निम्न-उत्सर्जन वाली औद्योगिक प्रणाली का विकास, v) कार्बन डाइऑक्साइड को दूर करने और उससे संबंधित अभियांत्रिकी समाधानों का विकास, vi) सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिक विचारों के अनुरूप वन और वनस्पति आवरण को बढ़ाना तथा vii) निम्न-कार्बन उत्सर्जन के साथ विकास करने के लिए आर्थिक और वित्तीय आवश्यकताएं।

भारत ने छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर करने के लिए "राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन" की घोषणा की है। जलवायु के अनुकूल विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए, यह मिशन स्वच्छ तकनीक के विनिर्माण में सहयोग करने के लिए है। इसका उद्देश्य घरेलू मूल्य संवर्धन में सुधार करना और सौर पीवी सेलों, ईवी बैटरियों, मोटरों और नियंत्रकों, इलेक्ट्रोलाइज़रों, पवन टर्बाइनों, अत्यधिक वोल्टेज ट्रांसमिशन वालें उपकरणों और ग्रिड स्केल बैटरियों के लिए हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुँचने में परमाणु ऊर्जा के महत्व को स्वीकार करते हुए, वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के विकास हेतु विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई है। परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत, वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित एसएमआर संचालित हो जाएँगे।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात में वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाने की भारत की महत्वाकांक्षा का परिचायक है। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हरित हाइड्रोजन की **5 मिलियन टन प्रति वर्ष** की लक्षित उत्पादन क्षमता हासिल करना है।

*****